16 जनवरी 2014

माननीय वित्त मंत्री की नाबार्ड के बोर्ड सदस्यों के साथ चर्चा

नई दिल्ली: माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में नाबार्ड के निदेशक मण्डल के सदस्यों को संबोधित किया और भारत सरकार की प्राथमिकताओं तथा शीर्ष विकास बैंक से अपेक्षाओं के संबंध में निदेशकों के साथ परामर्श किया. इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा भी उपस्थित थे.

इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के हस्तशिल्प और कारीगरों के उत्पादों के विपणन के लिए नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त ई-कॉमर्स पोर्टलों - www.ekraftsindia.com और www.shilpihaat.com का शुभारंभ किया.

इस अवसर पर, उन्होंने पूरे देश में स्वयं सहायता समूहों पर डिजिटाइजेशन के लिए रोडमैप का भी अनावरण किया. इस समय देश में 73 लाख स्वयं सहायता समूह हैं और डिजिटाइजेशन से प्रधानमंत्री जन धन योजना में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की सहभागिता में और अच्छी भागीदारी हो जाएगी. डिजिटाइजेशन से बैंकिंग प्रणाली के साथ स्वयं सहायता समूहों को बेहतर तरीके से संपर्क करने में भी सहायता मिलेगी.

माननीय वित्त मंत्री ने देश की भावी खाद्य संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए कृषि में दीर्घावधि निवेश की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय बजट से आवंटित किए गए दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि से रु 5000 करोड़ की प्रारंभिक कॉरपस का नाबार्ड ने बड़े अच्छे ढंग से उपयोग किया. नाबार्ड को उन्होंने वित्तीय समावेशन, छोटे और सीमांत किसानों को कृषि ऋण जैसे क्षेत्रों में अपना नेतृत्व जारी रखने के साथ ही उन किसानों (काश्तकारों तथा पट्टीदारों) इत्यादि को नाबार्ड सहायता प्रदान करना जारी रखे जिनके पास अपने खेतों से संबंधित स्वामित्व विलेख नहीं है.

इस अवसर पर बोलते हुए श्री जेटली ने कहा कि नाबार्ड ग्रामीण वित्त मार्केट में मौजूद कठिनाइयों का समाधान करना जारी रखें और इसके द्वारा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए शीर्ष विकास बैंक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखें.
ग्रामीण आवास के लिए सहायता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पुनर्वित्त के रुप में रूपये 3000 करोड़ का आबंटन यह दर्शाता है कि नाबार्ड ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास किया है तथा इन प्रयासों को बढ़ाए जाने पर भी बल दिया.

केंद्रीय वित्त मंत्री ने परियोजना विधि के रुप में पिछड़े जिलों के विकास के लिए नाबार्ड के जिला केंद्रित अवधारणा की तारीफ की और 10 पिछड़े जिलों में इस प्रायोगिक परियोजना के चलते अगले 3 वर्षो में प्रति व्यक्ति ग्रामीण ऋण दोगुना हो जाएगा.

श्री जयंत सिन्हा, वित्त राज्य मंत्री ने वाटरशेड विकास, आदिवासी विकास, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा की गई पहलों की सराहना की.

नाबार्ड के बोर्ड में भारत सरकार के कई सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, चुनिंदा राज्यों के अपर मुख्य सचिव शामिल रहते हैं तथा श्री एच के भनवाला इसके अध्यक्ष हैं.